

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 801
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

सेवानिवृत्ति के पश्चात् न्यायाधीशों को पद

801. श्री अभिषेक बनर्जी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश भर में न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् कुल कितने पदों की पेशकश की गई ;

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद के इन पदों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और किन-किन संस्थाओं अथवा निकायों में इनकी नियुक्ति की गई थी ;

(ग) सेवानिवृत्ति के बाद इन पदों पर न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए क्या मानदंड और प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(घ) सेवानिवृत्ति के बाद के पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (घ) : विभिन्न स्तरों पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या किसी अन्य इकाई द्वारा नियुक्त/विनियोजित किया जा सकता है । जो ऐसी नियुक्तियों/विनियोजनों को शासित करने वाले विद्यमान ढांचे पर निर्भर करता है । इस प्रकार ऐसी नियुक्तियां एक विकेन्द्रीकृत रीति में होती हैं और इसलिए मांगी गई जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती हैं ।
